पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री और संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) मध्य प्रदेश के सभी 45 जिला मुख्यालयों मे तारघर सुविधा मुहैया करवा दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नये डाकघर तथा शाखा डाकघरों का खोला जाना

788. **श्री राधा किशन मालवीय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में कितने नये डाकघर तथा शाखा डाकघर खोले जाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है; और

(ख) इन डाकघरों तथा उनके कर्मचारियों पर खर्च की जाने वाली राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री और संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) 1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 1000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 200 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव था। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के मानदण्डों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के सहयोग से संशोधित किया जा रहा है। जब तक मौजूदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक राज्यवार डाक नेटवर्क विस्तार कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। नए मानदण्ड निर्धारित हो जाने के बाद बजटीय प्रावधानों सहित राज्यवार ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सयोग से योजना आयोग ने डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए 1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपए के परिव्यय को अनुमोदित कर दिया है जिसके अन्तर्गत नए डाकघर खोलने का कार्यक्रम भी आ जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद की रिपोर्ट जनवरी, 1991 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाने की संभावना है।

Procedure for environment clearance

789. SHRI JITENDRABHAI LABH-SHANKER BHATT: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have submitted a set of proposals for rationalisation of environment clearance procedures which aim at "expanding the role of the Ministry" as reported in the Deccan Herald of 1st September, 1990, and

(b) if so, the details of improved procedure for environment clearance?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) and (b) Proposals for rationalisation of environmental impact assessment procedure have been under consideration with the following salient features:—

—Making environmental impact assessment a statutory requirement;

—Uniform coverage of both private as well as public sector projects;

—Delegation of powers for environmental clearance of certain categories of projects to state agencies.

The primary objective of these proposals is to rationalise the procedure rather than expand the role of the Ministry.

मंडल आयोग के प्रतिवेदन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों को हुई क्षति

790. **श्री प्रभाकर राव कलवला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने के विरोध में छात्रों द्वारा किए